भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1139
जिसका उत्तर बृहस्पतिवार, 20 दिसम्बर, 2018 को दिया जाना है

पूंजीगत वस्तुओं के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को मजबूत करना

1139. श्री विजयपाल सिंह तोमर:

श्री पि. भट्टाचार्य:

क्या भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें किः

(क) क्या सरकार ने पूंजीगत वस्तुओं के आयात को कम करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को मजबूत बनाने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पूंजीगत वस्तुओं के उद्योग के लिए तकनीकी सहायता और वर्तमान पंचवर्षीय योजना के दौरान आधुनिक औद्योगिक पार्क प्रदान करने के लिए कोई लक्ष्य तय किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या इस संबंध में कोई व्यवहार्यता अध्ययन कराया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) से (ङ): लोक उद्यम विभाग ने घरेलू और विदेशी, दोनों बाजारों में इनके प्रचालन का विस्तार करने और वैश्विक पहचान के रूप में उभरने के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) को सुगम बनाने के लिए महारत्न और नवरत्न योजनाएं आरंभ की हैं। महारत्न और नवरत्न सीपीएसईज के बोर्ड को पूंजीगत व्यय, संयुक्त उद्यमों/सहायक कंपनियों में निवेश, मानव संसाधन प्रबंधन, रणनीतिक समझौते करने/प्रौद्योगिकी संयुक्त उद्यमों, ऋण लेने और प्रौद्योगिकी तथा जानकारी आदि के क्षेत्रों में अधिक वित्तीय और प्रचलनात्मक अधिकार दिए गए हैं।

इसके अलावा, भारी उद्योग विभाग ने नवंबर, 2014 में 'भारतीय केपिटल गुड्स क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता की वृद्धि' के लिए एक योजना आरंभ की है। इस योजना का उद्देश्य अधिग्रहण और नवीनतम प्रौद्योगिकियों के विकास के माध्यम से भारतीय केपिटल गुड्स क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता की वृद्धि करना है। यह योजना प्रौद्योगिकी विकास हेतु उत्कृष्टता केन्द्रों, साझा इंजीनियरिंग सुविधा केन्द्रों (सीईएफसी) और क्षेत्र विशिष्ट एकीकृत औद्योगिक अवसंरचना सुविधा (आईआईआईएफ) की स्थापना के द्वारा केपिटल गुड्स क्षेत्र में प्रौद्योगिकीय गहनता का सृजन करती है। इस योजना में प्रौद्योगिकी के अधिग्रहण/अंतरण के लिए एक वित्तीय घटक, नामतः प्रौद्योगिकी अधिग्रहण निधि कार्यक्रम

(टीएएफपी) भी है। इसमें ₹581.82 करोड़ की बजटीय सहायता के साथ इसके अधिकांश संघटकों के कार्यान्वयन हेतु सार्वजनिक निजी भागीदारी की परिकल्पना है। यह योजना प्रयोक्ता उद्योग और शैक्षणिक क्षेत्र के सहयोग से स्वदेशी प्रौद्योगिकी और विनिर्माण के विकास, लागत प्रतिस्पर्धात्मकता, आयात में कमी, निर्यात में बढ़ोतरी और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित कर रही है।

अब तक, 'भारतीय केपिटल गुड्स क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता की वृद्धि' हेतु योजना के तहत उत्कृष्टता केन्द्रों हेतु 8 प्रस्ताव, सीईएफसी हेतु 10 प्रस्ताव, टीएएफपी हेतु 5 प्रस्ताव और आईआईआईएफ घटक हेतु एक प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है। आईआईआईएफ घटक के तहत कर्नाटक सरकार के सहयोग से टुमकुर, कर्नाटक के निकट एक एकीकृत मशीन टूल्स पार्क नामतः टुमकुर मशीन टूल्स पार्क की स्थापना की जा रही है।

जैसा कि मंजूरी देने से पूर्व योजना में परिकल्पना की गई है, सभी परियोजना प्रस्तावों की दो स्तरों पर जांच की जाती है।

*****